

आयुक्तालय (अपील-I) केंद्रीय उत्पादन शुल्क \* सातमाँ तल, केंद्रीय उत्पाद शुल्क भवन, पोलिटेकनिक के पास, आमबाबाडि, अहमदाबाद – 380015.

<u>रजिस्टर्ड डाक ए.डी. द्वारा</u>

ग

क फाइल संख्या : File No : V2(32)/50&51/Ahd-I/2016-17 प्रििटेट - परिट के Stay Appl.No. NA/2016-17

ख अपील आदेश संख्या Order-In-Appeal Nos. AHM-EXCUS-001-APP-051&052-2016-17 दिनाँक 30.01.2017जारी करने की तारीख Date of Issue <u>02</u>

<u>श्री उमा शंकर</u> आयुक्त (अपील-I) द्वारा पारित Passed by Shri. Uma Shanker, Commissioner (Appeal-I)

Deputy Commissioner, Div-III केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, Ahmedabad-I द्वारा जारी मूल आदेश सं MP/639 to 640/DC/2016-Reb. दिनॉक: 4/28/2016, से सृजित

Arising out of Order-in-Original No. MP/639 to 640/DC/2016-Reb. दिनाँक: 4/28/2016 issued by Deputy Commissioner, Div-III Central Excise, Ahmedabad-I

अपीलकर्ता का नाम एवं पता Name & Address of the Appellant / Respondent

#### M/s. Jagson Colorchem Ltd. Ahmedabad

कोई व्यक्ति इस अपील आदेश से असंतोष अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथास्थिति नीचे बताए गए सक्षम अधिकारी को अपील या पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

Any person a aggrieved by this Order-In-Appeal may file an appeal or revision application, as the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way :

#### भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन ः Revision application to Government of India :

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा अतत नींचे बताए गए मामलों के बारे में पूर्वोक्त धारा को उप–धारा के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अधीन सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली : 110001 को की जानी चाहिए।

(i) A revision application lies to the Under Secretary, to the Govt. of India, Revision Application Unit Ministry of Finance, Department of Revenue, 4<sup>th</sup> Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi - 110 001 under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid :

(ii) यदि माल की हानि के मामले में जब ऐसी हानि कारखाने से किसी भण्डागार या अन्य कारखाने में या किसी भण्डागार से दूसरे भण्डागार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भण्डागार या भण्डार में चाहे वह किसी कारखाने में या किसी भण्डागार में हो माल की प्रकिया के दौरान हुई हो।

(ii) In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse.

(b) In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.

(ग) यदि शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर (नेपाल या भूटान को) निर्यात किया गया माल हो।

... 2 ...

(ख) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उपयोग शुल्क कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क के रिबेट के मामलें में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित है।

- (b) In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.
- (ग) यदि शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर (नेपाल या भूटान को) निर्यात किया गया माल हो।
- (c) In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो डयूटी केडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिक आयुक्त, अपील के द्वारा पारित वो समय पर या बाद में वित्त अधिनियम (नं.2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हो।

- (d) Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec.109 of the Finance (No.2) Act, 1998.
- (1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपत्र संख्या इए–8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनाँक से तीन मास के भीतर मूल–आदेश एवं अपील आदेश की दो–दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए। उसके साथ खाता इ. का मुख्यशीर्ष के अंतर्गत धारा 35–इ में निर्धारित फी के भुगतान के सबूत के साथ टीआर–6 चालान की प्रति भी होनी चाहिए।

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(2) रिविजन आवेदन के साथ जहाँ संलग्न रकम एक लाख रूपये या उससे कम हो तो रूपये 200/– फीस भुगतान की जाए और जहाँ संलग्न रकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/– की फीस भुगतान की जाए।

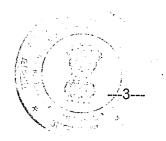
The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील:-Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35—बी / 35—इ के अंतर्गत:--

Under Section 35B/ 35E of CEA, 1944 an appeal lies to :-

- (क) वर्गीकरण मूल्यांकन से संबंधित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठिका वेस्ट ब्लाँक नं. ३. आर. के. पुरम, नई दिल्ली को एवं
- (a) the special bench of Custom, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No.2, R.K. Puram, New Delhi-1 in all matters relating to classification valuation and.



2

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise(Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of Rs.1,000/-, Rs.5,000/- and Rs.10,000/- where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asstt. Registar of a branch of any nominate public sector bank of the place where the bench of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated.

(3) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है तो प्रत्येक मूल ओदश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होते हुए भी कि लिखा पढी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner not withstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.

(4) न्यायालय शुल्क अधिनियम 1970 यथा संशोधित की अनुसूचि—1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उक्त आवेदन या मूल आदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रति पर रू.6.50 पैसे का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall a court fee stamp of Rs.6.50 paise as prescribed under scheduled-I item of the court fee Act, 1975 as amended.

इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्याविधि) नियम, 1982 में निहित है।

Attention in invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

(6) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण <u>(सिस्टेट)</u>, के प्रति अपीलो के मामले में कर्तव्य मांग (Demand) एवं दंड (Penalty) का 10% पूर्व जमा करना अनिवार्य है। हालांकि, अधिकतम पूर्व जमा 10 करोड़ रुपए है। (Section 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के अंतर्गत, शामिल होगा "कर्तव्य की मांग"(Duty Demanded) -

- (i) (Section) खंड 11D के तहत निर्धारित राशि;
- (ii) लिया गलत सेनवैट क्रेडिट की राशि;

(5)

والمتحدثة والمحافظة المتعاد والمحافظة المراجع والمحافظة المتحدينية والمحافظ المحتية والمحافظة والمحا

(iii) सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6 के तहत देय राशि.

⇒ यह पूर्व जमा 'लंबित अपील' में पहले पूर्व जमा की तुलना में, अपील' दाखिल करने के लिए पूर्व शर्त बना दिया गया है .

For an appeal to be filed before the CESTAT, 10% of the Duty & Penalty confirmed by the Appellate Commissioner would have to be pre-deposited, provided that the pre-deposit amount shall not exceed Rs.10 Crores. It may be noted that the pre-deposit is a mandatory condition for filing appeal before CESTAT. (Section 35 C (2A) and 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

(i) amount determined under Section 11 D;

(ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;

(iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

इस इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो माँग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती है।

In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute."

নর বয়

### **ORDER-IN-APPEAL**

M/s. Jagson Colorchem Limited, Plot No. 5601-4, Phase-II, GIDC, Vatwa, Ahmedabad, [*for -short - 'appellant*] has filed two appeals against OIO No. MP/639-640/DC/2016-Reb dated 28.4.2016, passed by the Deputy Commissioner, Central Excise, Division-III, Ahmedabad-I Commissionerate[for short - '*adjudicating authority*']. The appeal nos. are 50 & 51/Ahd-I/2016-17.

2. Briefly stated, the facts are that the appellant had filed a claim of Rs. 8,67,079/on 02.07.2015, seeking rebate in respect of goods exported vide ARE 1 Nos. 03/8.4.2014 and 50/7.5.2014, under rule 18 of the Central Excise Rules, 2002, read with notification No. 19/2004-CE(NT) dated 6.9.2004 and section 11B of the Central Excise Act, 1944.

3. As the rebate application was filed beyond one year and since it did not contain the original, duplicate and triplicate copy of ARE-1s and a declaration from the claimant and an NOC from the manufacturer, a show cause notice dated 30.11.2015 was issued asking the appellant to show cause as to why the rebate should not be rejected. This notice was adjudicated vide the impugned OIO dated 28.4.2016, wherein the adjudicating authority rejected the claim on the grounds that essential documents required for sanctioning the claim were not submitted and that the claim was submitted after the lapse of one year from the date of export.

4. Feeling aggrieved, the appellant has filed this appeal raising the following averments:

- that the only issue for consideration should have been whether rebate claims in question were submitted on 14.7.2014 as claimed by the appellant or whether the same were submitted on 2.7.2015;
- that the appellant themselves are manufacturer-exporter and they had themselves manufactured and exported the goods;
- that once a copy of receipt is produced before the learned adjudicating authority, it is his duty to find about the said receipt;
- that the appellant is not having original receipt but is having a photocopy of the same.

5. Personal hearing in the matter was held on 04.01.2017. Shri D.K.Trivedi, Advocate along with Shri Bheeksingh Solanki, appeared on behalf of the appellant, and reiterated the arguments made in the grounds of appeal.

6. I have gone through the facts of the case, the grounds of appeal and the oral averments, raised during the course of personal hearing.

7. The short question to be decided is whether the appellant is eligible for the said rebate.

8. As is evident, the appellant's contention is that the rebate claim was submitted on 14.7.2014. He has attached a photocopy of the receipt no. CEXDIV-III-AHD/000736/2014 issued on 14.7.2014 by the department, which lists the document as rebate claim in respect of ARE-1 No. 3 and 50/2014-15. The letter is addressed to Central Excise, Division-III, Ahmedabad-I. On this copy being produced before the adjudicating authority, as an evidence of the rebate claim being submitted on 14.7.2014, [within time, since the exports were made on 15.4.2014 and 11.5.2014], the adjudicating authority held as follows:

"I find that submission of the aforesaid claims by the claimant before the Divisional Assistant/Deputy Commissioners is incorrect as the register maintained in the division does not contain any such entry and when the rebate sanctioning authority does not have access to the documents required to sanction of rebate claim, how can the Assistant/Deputy Commissioner would be able to sanction the said claim. Further, original copy of receipt no. CEXDIV-III-AHD/000736/2014 dated 14.7.2014 was never produced by the claimant before the undersigned during the course of personal hearing therefore, authenticity of the photocopy of the receipt could not be verified."

I feel, that once the appellant has produced copy of the receipt purportedly issued by the department, documenting receipt of his rebate claim, it would have been prudent on the part of the adjudicating authority to conduct an inquiry rather than calling for the original copy of the receipt. As the receipt produced by the appellant is a system generated receipt, its genuineness can very well be verified from the *Sevottam* section. An inquiry would have revealed as to how the claim, said to have been submitted in the Sevottam section, was misplaced/missing. Questioning the receipt, without inquiry based on assumption, is unjust and improper and shirking of the official responsibility.

9. The appellant has submitted the proof of his having submitted the rebate claims on 14.7.2014. Since the rebate claim is submitted within the prescribed time limit, the impugned order rejecting the rebate claim on limitation, cannot be upheld.

10. In view of the foregoing, the impugned OIO is set aside and the appeal is allowed in view of the Sevottam receipt submitted by the appellant.

11.अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।11.The appeal filed by the appellant stands disposed of in above terms.

2 m gim

(उमा शंकर) आयुक्त (अपील्स - I)

Date :30.1.2017 Attested

(Vinod Dukose) Superintendent (Appeal-I) Central Excise Ahmedabad



# By RPAD

Τо,

M/s. Jagson Colorchem Limited, Plot No. 5601-4, Phase-II, GIDC, Vatwa, Ahmedabad

## Copy to:-

1. The Chief Commissioner, Central Excise, Ahmedabad Zone, Ahmedabad.

2. The Principal Commissioner, Central Excise, Ahmedabad-I.

3. The Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise Division-III, Ahmedabad-I. 4. The Additional Commissioner, System, Central Excise, Ahmedabad-I. Guard File.

b

6. P.A.

